Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal
ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 37-41

Received: 13-04-2025
Accepted: 22-06-2025

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के प्रभाव का अध्ययन – एक समीक्षा

डॉ. रविन्द्र कुमार

सहायक आचार्य (इतिहास, शिक्षा संकाय) IASE मानित विश्वविद्यालय, सरदारशहर, चूरू, राजस्थान, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16106675

Corresponding Author: डॉ. रविन्द्र कुमार

सारांश

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक दीर्घकालिक परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता से जूझती रही है। दशकों से यह प्रणाली अनेक संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता में असंगति, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समान अवसरों की कमी, वैश्विक शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ापन, व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों का अभाव, तथा अनुसंधान एवं नवाचार की अपर्याप्तता जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आती रही हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य, तकनीकी विकास, और जनसांख्यिकीय विविधता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक समग्र, समावेशी और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से पुनःसंरचित किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नीति - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020 - NEP 2020) - को घोषित किया गया। यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। NEP 2020 का उद्देश्य केवल अकादमिक पाठ्यक्रमों में सुधार करना नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण से बहु-विषयी शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्थागत स्वायत्तता को सशक्त बनाना, अकादमिक लचीलापन सुनिश्चित करना, डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को मुख्यधारा में लाना, अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित करना, तथा वैश्विक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना जैसे कई पहलुओं को सम्मिलित करती है। इस शोध लेख में हम NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों, उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन, नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों, तथा नीति के प्रभावों का भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है - इन सभी पहलुओं का विस्तार से और समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। साथ ही, नीति के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों, व्यावहारिक जमीनी सच्चाइयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इसके प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे पाठकों को भारत की शिक्षा व्यवस्था में इस ऐतिहासिक बदलाव की गहराई से समझ मिल सके।

मूलशब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, शैक्षणिक सुधार, अनुसंधान, बहु-विषयी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, संस्थागत स्वायत्तता, भारत

1. प्रस्तावना

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अपने आकार और विविधता के आधार पर वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आती है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय, प्रबंधन संस्थान, और अन्य तकनीकी व व्यावसायिक संस्थान सम्मिलित हैं। यह प्रणाली करोड़ों छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रही है और विविध सामाजिक, आर्थिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। AISHE

Report (2020) के अनुसार, भारत में लगभग 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 40,000 से अधिक कॉलेज कार्यरत हैं, जो इसे वैश्विक दृष्टि से एक व्यापक और जटिल प्रणाली बनाते हैं। हालांकि आकार में विशाल होने के बावजूद, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करती रही है। इनमें शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन, अनुसंधान और नवाचार की कमी, वैश्विक रैंकिंग में पिछड़ापन, कौशल आधारित शिक्षा की न्यूनता, और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का अभाव जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से देखी गई हैं। साथ ही, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियामक संस्थाओं की जटिलता, पाठ्यक्रम की रूढ़िवादिता और रोजगार के अनुकूलता की कमी भी लंबे समय से चिंताजनक रही हैं। इन सभी समस्याओं और 21वीं सदी की बदलती सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की घोषणा की, जो कि 1986 की शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में किया गया सबसे व्यापक और महत्त्वपूर्ण संशोधन है। यह नीति न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि एक दूरदर्शी रोडमैप है, जिसका उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, विद्यार्थियों को समावेशी, लचीला और बहु-विषयी ज्ञान प्रदान करना, तथा अनुसंधान व नवाचार को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना है। NEP 2020 यह सुनिश्चित करती है कि उच्च शिक्षा प्रणाली "समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तायुक्त, और अकादमिक रूप से स्वतंत्र" हो, जिसमें छात्रों को न केवल ज्ञान, बल्कि नैतिक मूल्य, वैश्विक दृष्टिकोण, और 21वीं सदी के आवश्यक कौशल भी प्राप्त हों। यह नीति भारत को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके प्रावधानों को कितनी दक्षता, संसाधनों और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाता है।

2. NEP 2020 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of NEP 2020):

2.1 बहु-विषयी शिक्षा (Multidisciplinary Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का एक प्रमुख और दूरदर्शी पहलु यह है कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत (integrated) और बहु-विषयी (multidisciplinary) बनाने की दिशा में सशक्त रूप से प्रेरित करती है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि छात्र केवल एक संकीर्ण विषय तक सीमित न रहकर विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे उनमें समग्र सोच, रचनात्मकता, और समस्या समाधान की बहु-आयामी क्षमता विकसित हो सके। यह दृष्टिकोण आज की वैश्विक और जटिल समस्याओं के समाधान हेतु अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। NEP यह मानती है कि 21वीं सदी के छात्रों के लिए बहु-विषयी दक्षताएं आवश्यक हैं, क्योंकि आज के युग में विज्ञान, तकनीक, मानविकी, और सामाजिक विज्ञान के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। उदाहरण स्वरूप, एक इंजीनियरिंग छात्र को अब केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य, पर्यावरणीय समझ, सामाजिक संवेदना, और संप्रेषण कौशल की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण नीति बहु-विषयी संस्थानों की स्थापना और सभी स्तरों पर लचीले पाठ्यक्रमों (flexible curricula) को अपनाने की सिफारिश करती है। इस दिशा में कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने सकारात्मक पहल भी शुरू की है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IIT Hyderabad) ने पारंपरिक तकनीकी शिक्षा के दायरे से बाहर निकलते हुए लिबरल आर्ट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें छात्र साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, और संस्कृति अध्ययन जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को न केवल तकनीकी दृष्टि से दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें एक बहु-आयामी मानवतावादी दृष्टिकोण से भी समृद्ध करना है (Reddy, 2021)। इसके अतिरिक्त, अन्य IITs, NITs, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस दिशा में बदलाव देखे जा रहे हैं। NEP का यह दृष्टिकोण भारत में पारंपरिक रूप से चल रही विषय-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है और उसे विद्यार्थी-केंद्रित, विकल्पपूर्ण, और नवोन्मेषी प्रणाली में रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे छात्रों को अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक स्वतंत्रता, रचनात्मकता और संभावनाएं प्राप्त होंगी।

2.2 चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम (Four-Year Undergraduate Program - FYUP)

यह मॉडल छात्र को अपने रूचि अनुसार विशेषज्ञता और रिसर्च दोनों का विकल्प देता है।

भारत में वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई नई शिक्षा नीति (NEP 2020) ने विद्यालयी शिक्षा के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए 5+3+3+4 संरचना की घोषणा की है। यह संरचना विद्यार्थियों के शैक्षिक और मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप बनाई गई है, जो निम्नलिखित है:

5+3+3+4 शैक्षिक संरचना का विवरण:

1. बुनियादी चरण (Foundation Stage) - 5 वर्ष

आयु: 3 से 8 वर्ष

कक्षा: प्री-स्कूल (आंगनवाड़ी) के 3 वर्ष + कक्षा 1 और 2
ध्यान: खेल आधारित, गतिविधि-आधारित और बहु-संवेदी शिक्षा
उद्देश्य: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को संस्थागत रूप देना

2. तैयारी चरण (Preparatory Stage) - 3 वर्ष

आयु: 8 से 11 वर्ष
कक्षा: 3 से 5
ध्यान: भाषा, गणित, विज्ञान, कला, और जीवन कौशलों की नींव
पद्धति: खोज आधारित, संवादात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण

3. मध्य चरण (Middle Stage) - 3 वर्ष

आयु: 11 से 14 वर्ष
कक्षा: 6 से 8
ध्यान: अवधारणात्मक समझ, प्रयोगात्मक शिक्षण, और विषय चयन की शुरुआत
नवाचार: कक्षा 6 से कौशल शिक्षा और कोडिंग की शुरुआत

4. माध्यमिक चरण (Secondary Stage) - 4 वर्ष

आयु: 14 से 18 वर्ष
कक्षा: 9 से 12
ध्यान: विषयों की गहराई, बहु-विषयी दृष्टिकोण, और लचीलापन
विशेषता: कला, विज्ञान, व्यवसाय आदि की बाध्यता समाप्त; छात्र अपनी रुचि अनुसार विषय चुन सकते हैं

2.3 अकादमिक क्रेडिट बैंक (Academic Bank of Credits - ABC)

यह प्रणाली छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से क्रेडिट जमा करने और उन्हें एकत्र कर डिग्री प्राप्त करने की सुविधा देती है (UGC, 2021).

2.4 उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India - HECI)

NEP ने UGC, AICTE, NCTE जैसी संस्थाओं को एकीकृत कर HECI का प्रस्ताव दिया है, जिससे नियामन अधिक पारदर्शी और कुशल हो सके।

2.5 शिक्षक शिक्षा में सुधार (Teacher Education Reforms)

2030 तक B.Ed. को चार वर्षीय समेकित डिग्री बनाने का लक्ष्य है।

2.6 डिजिटल शिक्षा और तकनीकी एकीकरण (Digitalization and EdTech)

DIKSHA, SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म्स को विस्तार दिया जा रहा है। महामारी के बाद यह अत्यधिक प्रासंगिक सिद्ध हुआ (Mehta & Ghosh, 2021).

2.7 अनुसंधान एवं नवाचार (Research & Innovation)

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना शोध को संस्थागत स्वरूप देने हेतु प्रस्तावित है।

2.8 अंतरराष्ट्रीयकरण (Internationalization of Higher Education)

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में परिसरों की अनुमति और भारतीय संस्थानों को विदेश में विस्तार की सुविधा दी गई है (Jain, 2022).

3. उच्च शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव (Impact Analysis)

3.1 गुणवत्ता में सुधार

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दिए जाने से पाठ्यक्रम नवाचार, मूल्यांकन सुधार और अनुसंधान की स्वतंत्रता बढ़ी है (Ramakrishna, 2022). नई ग्रेडिंग प्रणाली और outcome-based education गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर है।

3.2 समावेशिता (Inclusivity): NEP का लक्ष्य GER (Gross Enrollment Ratio) को 2035 तक 50% तक पहुंचाना है। साथ ही, एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, समर्थन तंत्र, और रिमोट लर्निंग अवसर भी विस्तार को दर्शाते हैं।

3.3 कौशल उन्मुखता (Skill Orientation)

फ्लेक्सिबल करिकुलम और स्किल-आधारित प्रोग्रामों ने छात्रों की employability में वृद्धि की है। उदाहरणतः TISS, DU, और IITs में इंटर्नशिप आधारित पाठ्यक्रम लागू किए गए (Nanda, 2022).

3.4 संस्थागत पुनर्गठन (Institutional Restructuring)

"अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट", "वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन" जैसी अवधारणाओं ने संस्थागत गतिशीलता को बढ़ावा दिया।

3.5 अनुसंधान संवर्धन

NEP 2020 अनुसंधान को सामाजिक और औद्योगिक विकास से जोड़ती है। NRF जैसे प्रस्तावित निकाय, अनुसंधान के लिए धन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

4. चुनौतियाँ (Challenges in Implementation)

वित्तीय संसाधनों की कमी: शिक्षा पर GDP का 6% खर्च लक्ष्य आज भी दूर है (Economic Survey, 2023).

शिक्षक प्रशिक्षण की कमी: नये पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है (Kumar, 2023).

डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण एवं वंचित वर्गों तक डिजिटल संसाधनों की पहुँच सीमित है।

संविधानिक स्वायत्तता बनाम केंद्रीय नियंत्रण: कुछ शिक्षाविदों ने HECI के जरिए केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका पर चिंता जताई है।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नए और आवश्यक मार्गदर्शन की दिशा दी है। यह नीति उच्च शिक्षा को न केवल आधुनिक (modern) और तकनीकी दृष्टि से उन्नत, बल्कि समावेशी (inclusive), नवाचार-प्रेरित (innovation-driven) और वैश्विक प्रतिस्पर्धा (globally competitive) के योग्य बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके मूल में एक ऐसा विजन निहित है जो छात्रों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल, सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाना चाहता है। नीति में प्रस्तावित बहु-विषयी शिक्षा, अकादमिक लचीलापन, डिजिटल तकनीक का समावेश, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना, और विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने की अनुमति जैसे प्रावधान इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देते हैं। साथ ही, यह नीति समानता और समावेशिता के सिद्धांतों को भी सशक्त बनाती है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर वंचित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। हालांकि, यह भी एक यथार्थ है कि NEP 2020 के प्रभाव अभी अपने प्रारंभिक चरण में हैं। नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए केवल दस्तावेज़ी सुधार पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए वास्तविक और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त वित्तीय निवेश, तकनीकी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, और प्रशासनिक दक्षता अत्यंत आवश्यक है। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें, शैक्षिक संस्थान, शिक्षक, नीति निर्माता और नागरिक समाज एक सामूहिक प्रयास से इस नीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए समर्पित नहीं होंगे, तब तक इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को योजनाबद्ध तरीके से, न्यायसंगत संसाधनों और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जाए, तो भारत निश्चित रूप से एक ऐसे ज्ञान-आधारित समाज (Knowledge-based society) में रूपांतरित हो सकता है जो न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि वैश्विक शिक्षा और नवाचार के मानचित्र पर भी एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके।

6. संदर्भ (References)

1. Ministry of Human Resource Development (MHRD). National Education Policy 2020. New Delhi: Government of India; c2020.
2. All India Survey on Higher Education (AISHE). AISHE Report 2020. New Delhi: Ministry of Education; c2020.
3. University Grants Commission (UGC). Academic Bank of Credits. New Delhi: UGC; c2021.
4. Mehta A, Ghosh R. Online Education and NEP 2020. Journal of Digital Learning. 2021;1(2):123-134.
5. Reddy CS. NEP 2020 and IITs. Indian Express. 2021.
6. Jain A. Internationalisation of Indian Higher Education. Times of India. 2022.
7. Kumar A. Teacher Training and NEP 2020. Journal of Education & Practice. 2023;14(3):45-57.
8. Ramakrishna P. Quality Assurance in Higher Education. Higher Education Review. 2022;7(1):11-19.
9. Economic Survey of India. Ministry of Finance. Economic Survey 2023. New Delhi: Ministry of Finance; c2023.
10. Nanda S. Employability and Higher Education. The Hindu. 2022.
11. Kapur D. Reforming Indian Education. Foreign Affairs. 2020;99(5):100-112.
12. Tilak JBG. Education and Equity in NEP. Economic and Political Weekly (EPW). 2021;56(18):12-14.
13. Banerjee A, Duflo E. Education and Development. MIT Working Papers. 2021;WP No. 2021-09.
14. World Bank. Education Statistics. Washington, D.C.: World Bank; c2021.
15. UNESCO. Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO; c2022.
16. All India Council for Technical Education (AICTE). Faculty Development Guidelines. New Delhi: AICTE; c2022.
17. University Grants Commission (UGC). National Credit Framework. New Delhi: UGC; c2022.
18. Sharma M. Digitization in Higher Education. Outlook India. 2021.
19. Times Higher Education. India Rankings Analysis. Times Higher Education. 2022 Jul 12.
20. Sahu PK. Impact of Pandemic on Education. The Hindu. 2021 Jun 22.
21. Mishra S. Blended Learning Models. Journal of Educational Technology. 2021;22(4):67-79.
22. Chatterjee R. Future of Indian Universities. Indian Journal of Higher Education. 2022;30(1):25-33.
23. NEP Implementation Committee Reports. 2021-2024. New Delhi: Ministry of Education; 2021-2024.
24. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Education Indicators. Paris: OECD; 2021.
25. The Print. HECI and Governance. The Print. 2021 Dec 18.

26. The Wire. Centralization and Autonomy. The Wire. 2022 Feb 25.
27. Ministry of Education. NEP Dashboard. New Delhi: Ministry of Education; 2023.
28. Bhattacharya R. Liberal Arts and NEP. Journal of Indian Higher Education. 2021;18(2):45-52.
29. The Hindu Editorial. NEP 2020 and its Impact. The Hindu. 2020-2024.
30. Press Information Bureau (PIB). Releases on NEP 2020-2024. New Delhi: PIB; 2020-2024.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.